

यूपी के सभी जिलों में बनेंगे एआई केंद्र

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने और शासन व नागरिक सेवाओं में एआई के सुरक्षित, प्रभावी एवं उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन (यूपी-एआईएम)' की स्थापना, क्रियान्वयन एवं संचालन को मंजूरी दी गई।

मिशन के तहत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट एआई केंद्र विकसित किए जाएंगे। ये केंद्र स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित नवाचार, प्रशिक्षण, रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च प्रोजेक्ट, इनोवेशन चैलेंजेस और



05 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा
100 एआई स्टार्टअप को बढ़ावा

■ योगी कैबिनेट की बैठक में यूपी-एआईएम को दी गई मंजूरी

हैकथॉन्स के माध्यम से अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए एआई ट्रस्ट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क भी विकसित होगा। इसमें हाई-इम्पैक्ट सरकारी एआई समाधानों के लिए सुरक्षा, गोपनीयता, जोखिम मूल्यांकन, प्री-डिप्लॉयमेंट असेसमेंट और मानव पर्यवेक्षण पर विशेष जोर रहेगा। स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में होगा संचालन। यूपी-एआईएम को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन के लिए एपेक्स

बॉडी, गवर्निंग बॉडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था होगी। मिशन का नेतृत्व सीईओ करेंगे। यूपी एआई स्टैक के विकास और संचालन के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) का चयन किया जाएगा। एमएसआई द्वारा एआई स्टैक और एआई सॉल्यूशन का डिजाइन, विकास, इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, संचालन एवं रखरखाव किया जाएगा, जिसकी समीक्षा एसएलए और निर्धारित माइलस्टोन के आधार पर की जाएगी। भविष्य में यूपी एआई स्टैक ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म सभी विभागों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।